लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4384

19 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

जूट प्रसंस्करण उद्योग

4384. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्यरत जूट प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या क्या है और साथ ही उनका राज्य-वार उत्पादन कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यातित वस्त्र उत्पादों का ब्यौरा क्या है और इससे उद्योग/देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार धीमी वृद्धि और अन्य निर्यात वाले जूट प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने में विफल रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार जूट उद्योगों को वैश्विक बाजार से प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में अधिशेष जूट उत्पादन के मद्देनजर किसानों को उनकी पैदावार का अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(च) जूट उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम और योजनाएं बनाई गई हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): इस समय देश में कुल 75 पटसन मिलें कार्यशील हैं। प्रचालन की स्थिति सहित उनके उत्पादन का ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

(ख): गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए वस्त्र उत्पादों का ब्यौरा क्या है और इसके माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा का उद्योग-वार/देश-वार ब्यौरा अनुबंध-।। में दिया गया है।

(ग) से (च): वस्त्र मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। उद्योग में नए निवेश करने के लिए यह योजना सहायक रही है। संयंत्र एवं मशीनरी अधिग्रहण प्रोत्साहन योजना (आईएसएपीएम) पटसन मिलों की मशीनों की लागत का 20% और एमएसएमई-जेडीपी इकाइयों को 30% की दर से प्रोत्साहन के साथ वर्ष 2013 में लागू की गई है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पटसन मिलों और जेडीपी इकाइयों को 4971.19 लाख रुपए की पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है।

जब कभी कच्ची पटसन का बाजार मूल्य एक निश्चित स्तर से नीचे चला जाता है तो भारतीय पटसन निगम पटसन किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उनसे कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के आधार पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कच्ची पटसन की खरीद करता है। सीएसीपी प्रत्येक वर्ष के लिए एमएसपी की सिफारिश देने से पहले मुद्रास्फिति से बचने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों की राय तथा सभी अंशदाताओं में कारक पर विचार करती है। इसके अलावा, पटसन क्षेत्र के उत्थान के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित अन्य योजनाएं अनुबंध-।।। में दी गई हैं।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा जूट प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में दिनांक 19.07.2019 पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4384 के भाग (क) में उल्लिखित **अनुबंध-I**

पटसन उत्पादों के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा

2018-19 (अप्रैल-मार्च)					***(मात्रा हजार मी.टन में)***
राज्य	**हैसियन**	**सैकिंग**	**अन्य**	**कुल**	**रिटर्न प्रस्तुत करने वाली प्रचालनशील पटसन मिलों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	0.0	30.0	4.4	34.4	7
उत्तर प्रदेश	2.8	1.7	1.1	5.6	1
बिहार	0.0	0.0	0.0	0.0	1*
ओडिशा	0.0	5.6	5.0	10.6	2
असम	0.1	10.3	0.0	10.4	2
छत्तीसगढ़	0.0	11.8	0.0	11.8	1
त्रिपुरा	0.0	0.3	0.0	0.0	1
पश्चिम बंगाल	144.7	852.9	90.8	1088.4	60
कुल	***147.6***	***912.6***	***101.3***	***1161.2***	***75***

* मिल ने रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए उत्पादन शून्य दर्शाया गया है।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा जूट प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में दिनांक 19.07.2019 पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4384 के भाग (ख) में उल्लिखित **अनुबंध-II**

उद्योग-वार वस्त्र निर्यात (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वस्तु	2016-17	2017-18	2018-19	अप्रैल-मई (2019-20)
सूती वस्त्र	10,429	11,190	12,429	1,686
मानव निर्मित वस्त्र	5,152	5,388	5,563	891
ऊन/ऊनी वस्त्र	175	186	222	36
रेशम उत्पाद	76	69	77	12
हथकरघा उत्पाद	360	356	344	62
कालीन	1,490	1,429	1,486	231
पटसन उत्पाद	321	342	330	52
कुल उत्पाद	**18,004**	**18,961**	**20,451**	**2,972**

स्रोत:डीजीसीआईएंडएस

देश-वार वस्त्र निर्यात (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

देश	2016-17	2017-18	2018-19	अप्रैल-मई (2019-20)
यूएसए	3515	3604	3962	613
बांग्लादेश	2035	2257	2325	288
चीन	1490	1160	1976	202
पाकिस्तान	605	665	658	56
यूके	532	541	578	92
तुर्की	553	734	577	90
वियतनाम	385	550	573	43
श्रीलंका	503	501	550	88
जर्मनी	587	606	544	86
यूएई	701	513	460	84
शेष विश्व	7,097	7,829	8,248	1,328
कुल वस्त्र उत्पाद	**18,004**	**18,961**	**20,451**	**2,972**

स्रोत:डीजीसीआईएंडएस

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ. सुभाष रामराव भामरे, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा जूट प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में दिनांक 19.07.2019 पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4384 के भाग (घ) में उल्लिखित **अनुबंध**-III

पटसन कामगारों के कल्याण, पटसन उद्योग के विकास, पटसन उत्पादकों की समस्याओं का समाधान करने और पटसन की उत्पादकता और निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम/योजनाएं:

(i) <u>पटसन सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग:-</u>

पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के तहत सरकार ने वस्तुओं और उस सीमा को विनिर्दिष्ट किया है जिसे उन्हें पटसन सामग्री में अनिवार्य रूप से पैक किया जाना है। इस समय पटसन पैकिंग में अनिवार्य पैक किए जाने के लिए खाद्यान्नों का कम से कम 100% और चीनी का कम से कम 20% पटसन पैकिंग में पैक किया जाना अनिवार्य है।

(ii) कामगार कल्याण योजना:

(क) स्वच्छता अभियान-सुलभ शौचालय:

एनजेबी, पटसन मिल कामगारों की साफ-सफाई, स्वास्थ्य सुविधा और काम करने की स्थितियों में सुधार करने के लिए पटसन मिलों को सहायता प्रदान करती है। सहायता की दर 60.00 लाख रुपए (प्रति मिल/वार्षिक) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय का 90% है। इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 46 पटसन मिलों में 1365 शौचालयों का निर्माण किया गया है।

(ख) पटसन मिलों के कामगारों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति की योजना, जेडीपी-एमएसएमई:

एनजेबी, पटसन मिलों/जेडीपी-एमएसएमई इकाईयों के कामगारों की बालिकाओं के उच्चतर और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान पटसन मिलों/जेडीपी एमएसएमई कामगारों की 17,722 बालिकाओं के उच्चतर और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में सफल होने पर 1133.05 लाख रुपए की छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

(iii) पटसन-आईसीएआरई (पटसन : बेहतर फसल और उन्नत रेटिंग प्रक्रिया):

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी), भारतीय कपास निगम लि. (जेसीआई) और केन्द्रीय पटसन और संबद्ध फाइबर अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ), कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर विगत चार वर्षों से चरणबद्ध ढंग से पटसन-आईसीएआरई (बेहतर फसल और उन्नत रेटिंग प्रक्रिया) नामक पटसन किसान कल्याण योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें वर्ष 2018-19 तक पटसन उत्पादक राज्यों के 69

ब्लॉकों को शामिल किया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को प्रमाणित बीजों का प्रयोग कर, पटसन की खेती में वैज्ञानिक तकनीक और अच्छी किस्म की पटसन का उत्पादन करने के लिए रेटिंग अपनाकर पटसन का उत्पादन करने और पटसन किसानों के लिए उत्पादकता बढ़ाने तथा पटसन उत्पादन की लागत को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

(iv) विपणन संवर्धन सहायता:

पटसन कारीगरों, उद्यमियों, बुनकरों, एनजीओ, महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) को भारत और विदेशों में अपने उत्पादों को बेचने विपणन और संवर्धन करने के लिए विपणन संवर्धन सहायता प्रदान की जाती है। एनजेबी द्वारा आयोजित मेले, इन समूहों के लोगों के लिए आजीविका के माध्यम हैं। अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे-आईआईटीएफ, दिल्ली सूरजकुंड मेला, टेक्सट्रेंड्स, दिल्ली, ताज महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, शिल्पग्राम उदयपुर, गिफटेक्स, मुंबई, भारतीय शिल्प और उपहार मेला, ग्रेटर नोएडा आदि हैं जहां राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, पटसन उत्पादों के संवर्धन के लिए पटसन इकाइयों की भागीदारी का आयोजन करता है और उसे सुकर बनाता है। विपणन संवर्धन सहायता के लाभार्थी जेडीपी इकाइयां, पटसन मिलें, डब्ल्यूएसएचजी आदि हैं। विपणन संवर्धन मेलें/प्रदर्शनियां, समूचे देश में आयोजित की जाती हैं और उनमें भागीदरी की जाती है। एनजेबी, निर्यात बढ़ाने के लिए पटसन निर्यातकों को निर्यात संवर्धन सहायता भी प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय मेलों, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) में भागीदारी को सुकर बनाता है।

(v) डिजाइन विकास योजना-एनआईडी में एनजेबी पटसन डिजाइन सैल:

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद के प्राकृतिक फाइबर के नवाचार केन्द्र (आईसीएनएफ) में पटसन शॉपिंग बैग और लाइफ स्टाइल एक्सेसरीज के विकास के लिए पटसन डिजाइन सैल स्थापित किया गया है।

(vi) पटसन एकीकृत विकास योजना (जेआईडीएस):

जेआईडी योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने के लिए लाभार्थी निकायों के साथ मिलकर समूचे देश के दूरदराज के स्थानों में स्थानीय इकाइयां और एजेंसियां स्थापित करना है। जेआईडी एजेंसियां, मूलस्तर पर मुख्यत: प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और डिजाइन/उत्पाद विकास तथा प्रसार करने के लिए मौजूदा और संभावित उद्यमों को बुनियादी,अग्रिम और डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा बैकवर्ड और फार्वर्ड लिंकेज प्रदान करने हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है।

(vii) पटसन कच्ची सामग्री बैंक (जेआरएमबी) योजना:

इस योजना को स्थानीय आधार पर छोटे और अतिलघु कारीगरों/उद्यमियों को कच्ची पटसन सामग्री उपलब्ध कराना है जो देश में विकेन्द्रीकृत जेडीपी क्षेत्र की मौजूदा आवश्यकता और संपोषणीयता के अनुकूल है।

(viii) निर्यात विपणन विकास सहायता योजना:

निर्यात विपणन विकास सहायता योजना (ईएमडीए), जीवनशैली और अन्य जेडीपी का निर्यात संवर्धन करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों और व्यापार प्रतिनिधिमंडल में भाग लेने हेतु पटसन उत्पादों के पंजीकृत विनिर्माताओं और निर्यातकों को सुविधा प्रदान करती है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान इस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए पंजीकृत निर्यातकों को 17.21 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।

(ix) विविधीकृत पटसन उत्पादों की खुदरा दुकानें और थोक आपूर्ति योजना:

खुदरा दुकान योजना, चयनात्मक और बड़े पैमाने पर खपत के लिए पटसन उद्यमियों द्वारा जेडीपी की आपूर्ति श्रृंखला और थोक आपूर्ति की सहायता करती है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान इस योजना के तहत 80 लाभार्थियो/उद्यमियों को 347.90 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

*****